



Bhumi Pednekar's Romantic Comedy...

SHARE	
सेंसेक्स	: 78,058.16
निफ्टी	: 23,603.35

SARAFSA	
सोना	: 8,210
चांदी	: 107.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

जैक के नए अध्यक्ष बने डॉ. नटवा हांसदा



**RANCHI :** हेमंत सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रांची के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डॉ. नटवा हांसदा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्य शिक्षा प्रणाली में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डॉ. हांसदा के पास शिक्षा के क्षेत्र में काफी अनुभव है और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों की भी गहरी समझ है। उनकी नियुक्ति ने राज्य के शैक्षिक ढांचे को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादातर की तिथि से उनका कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। उम्मीद की जा रही है कि डॉ. हांसदा के नेतृत्व में झारखंड एकेडमिक काउंसिल शैक्षिक उन्नति और सुधार की दिशा में नई पहल करेगी। बांग्लादेश ने भारत के समक्ष दर्ज कराया विरोध



**DHAKA :** बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत प्रवास के दौरान दिये गये झूठे और मनगढ़ंत बयानों को लेकर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने यहां यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम हसीना द्वारा बुधवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से दिए गए भाषण के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ संगठित तौर पर प्रतिरोध का आह्वान किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने भारत सरकार के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों पर लगातार की जा रही झूठी मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

# राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने दिया जवाब ‘सबका साथ, सबका विकास’ हमारा मूलमंत्र कांग्रेस के लिए ‘परिवार प्रथम’ : प्रधानमंत्री

## कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का लगाया आरोप, विपक्ष ने जताया विरोध

NEW DELHI (BHASHA) :

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब दिया। कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ उनकी सरकार का मूलमंत्र रहा है, जबकि कांग्रेस का मूलमंत्र ‘परिवार प्रथम’ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था, जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार परिवारवाद, तुष्टीकरण आदि का चालमेल था। कांग्रेस के मॉडल में परिवार प्रथम ही सर्वोपरि है। इसलिए, उनकी नीति-रिति, वाणी-वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दी।

तकरीबन 91 मिनट के अपने संबोधन का अधिकतर हिस्सा प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आपातकाल और कथित कुशासन सहित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर केंद्रित रखा और कहा कि उसके हृदय में



राज्यसभा में बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

**कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री का जिक्र**  
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री ने माना था कि लाइसेंस व परमिट के बिना कोई काम नहीं होता और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्तों के नहीं होता है। उन्होंने दावा किया कि उच्च सदन में कांग्रेस के एक सदस्य मौजूद हैं, जिनके पिताजी कार खरीदना चाहते थे और उनके पास पैसे भी थे, लेकिन 15 साल तक उन्हें कार खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ा था और वह भी कांग्रेस के ही राज में।

मुक्त होकर देश आज ‘चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को पहचानने लगी है। आज दुनिया हमें तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रही है। हम अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच-छह दशकों तक

लोगों के पास वैकल्पिक मॉडल नहीं था, लेकिन वह बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 2014 के बाद देश को एक नया मॉडल देखने को मिला, जो तुष्टीकरण पर आधारित नहीं है, बल्कि ‘संतुष्टीकरण’ पर आधारित है। **संसाधनों के अधिकतर प्रयोग पर ध्यान :** मोदी ने कहा कि भाजपा नीत सरकार संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवंत मीडिया और लोकतंत्र वाले देश ने उन्हें तीसरी

**पीएम के भाषणा में हमें गालियां देने के अलावा कुछ नहीं : कांग्रेस**  
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सिर्फ हताशा और कुंठा से भरी बातें कीं। मुख्य विपक्षी दल को गालियां देने के अलावा कोई नई बात नहीं की। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने संसद परिसर में कहा, लगता है कि प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए कोई संदेश भी नहीं बचा है। वह अपनी सरकार के कामकाज से पूरी तरह निराश हैं, इसलिए सिर्फ कांग्रेस को गाली देते रहे।

**हथकड़ी पहनकर विपक्षी नेताओं ने किया प्रदर्शन**  
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अमेरिका से 100 से अधिक अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजे जाने और उनके साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव और विरोध प्रदर्शन में शामिल कई अन्य विपक्षी सांसदों



संसद के बाहर हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करते विपक्ष के नेता

पीटीआई

ने अपने हाथों में हथकड़ी पहन रखी थी। उन्होंने देश का अपमान नहीं सहेंगे और मोदी सरकार

हाथ-हाथ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थीं।

उनकी (कांग्रेस) राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने एससी-एसटी कानून को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और उसको बढ़ाया भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार उनके नेतृत्व वाली सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से सामान्य वर्ग के गरीब को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया और वह भी बिना किसी

तनाव के और किसी से छीने बिना दिया। **बाबा साहेब को भारत रत्न देने का उल्लेख :** पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बाबा साहेब को कभी भी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने, सर्व-समाज ने बाबा साहेब की भावना का आदर किया। तब आज कांग्रेस को मजबूरन 'जय भीम' बोलना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया।

# मां काली की शरण में सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता के कालीघाट मंदिर में की पूजा

## स्टील प्लांट खुलने से लगभग 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

RANCHI (BHASHA) :

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं। गुरुवार को वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन (विधायक, गांडेय) के साथ कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे। हेमंत सोरेन ने ह्वाइट एंड ब्लू स्ट्राइप वाली टी-शर्ट और पैट पहन रखी थी। कल्पना मूर्मु सोरेन सफेद सलवार सूट में थीं। उन्होंने सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा भी रखा था।

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने काली मंदिर के गर्भगृह में एक साथ मां काली की पूजा-अर्चना की। कालीघाट के पंडा ने मंत्रोच्चार करवाया। दोनों ने मिलकर मां काली के चरण स्पर्श किए। उनके साथ झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी और



कोलकाता के कालीघाट में पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

अन्य वरीय पदाधिकारी भी थे। पंडा ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कंधे पर चुनरी डाली। मंदिर से बाहर निकलने तक चुनरी दोनों के कंधे पर थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश और राज्य के विकास में कई लोगों की

भागीदारी होती है। हमारे राज्य में कई लोग निवेश करते हैं। बंगाल और झारखंड में कई समानताएं हैं। यह पूछने पर कि क्या झारखंड में भी बंगाल की तरह निवेशक सम्मेलन करेंगे, उन्होंने कहा कि झारखंड में तो लोग ऐसे ही रुचि रखते हैं।

हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के न्यते पर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने बुधवार को इस समिट में झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन किया था। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में झारखंड को 26 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिससे 15 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता स्थित शक्तिपीठ कालीघाट में मां काली के दर्शन किए। दोनों ने गर्भगृह में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने झारखंड राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि एवं शांति के साथ-साथ राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना भी की।



**GWALIOR :** गुरुवार को वायुसेना का एक मिराज-2000 लड़ाकू विमान सिस्टम में खराबी के कारण मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें मामूली चोट आई और उन्हें हेलीकॉप्टर से ग्वालियर ले जाया जा रहा है। ‘सेंट्रल एयर कमान’ के प्रवक्ता ने बताया कि दोपहर करीब दो बजकर 40 मिनट पर बरहेटा सानी गांव के पास खेत में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो सीट वाले प्रशिक्षण विमान में आग लग गई। उन्होंने बताया कि विमान में खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट किया, आज नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान शिवपुरी (ग्वालियर) के पास भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 विमान सिस्टम में खराबी आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।

## गंभीर चिंता बीजों के अंकुरण और संपूर्ण विकास पर संकट की स्थिति

# कृषि क्षेत्र की राह का बड़ा रोड़ा बन रहा जलवायु परिवर्तन

PHOTON NEWS RESEARCH DESK :

जलवायु परिवर्तन के कारण सभी जीवों की जीवन पद्धति पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वायुमंडल का नेचुरल तापमान अधिक होने की वजह से पौधों के अंकुरण और उनके संपूर्ण विकास की स्थिति बदल रही है, जो ईकोसिस्टम के लिए तो गंभीर चिंता की बात है ही, हमारे कृषि क्षेत्र और फसलों के उत्पादन को भी इसकी भार झेलनी पड़ रही है। हाल में हुए विशेष रिसर्च के दौरान इस तरह की जानकारी विस्तार से साझा की गई है। रिसर्च में यह बात उभरकर सामने आई है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के समय में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। नॉर्थवेस्टर्न और ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के ताजी अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि तापमान में बढ़ोतरी के कारण बीजों के अंकुरण के समय में बदलाव आ रहा है, जिससे वनस्पति समुदायों की संरचना प्रभावित हो रही है। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है।

## शोधकर्ताओं ने अपने विशेष अध्ययन में ऐसे हालात की दी है विस्तृत जानकारी

- नॉर्थवेस्टर्न और ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार, बदल रही है पौधों की संरचना
- ईकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित आर्टिकल में किया गया है व्यावहारिक विश्लेषण
- कुछ पौधों की प्रजातियों के बीज अपेक्षित समय के पहले ही हो जाते अंकुरित
- समय के पहले अंकुरण के कारण कुछ पौधे अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं बड़े
- दूसरे छोटे पौधों को पानी और पोषक तत्व आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाते उपलब्ध
- पौधों के असमान विकास के कारण उत्पादन पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव



**अन्य जीवों पर भी दिखता है प्रभाव**  
अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जो पौधे जल्दी अंकुरित होते हैं, वे आकार में बड़े हो सकते हैं और इस कारण वे अधिक सूरज की रोशनी, पोषक तत्व और पानी हासिल कर पाते हैं। इससे बाद में अंकुरित होने वाले पौधों के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है। यह प्रतिस्पर्धा पौधों के साथ-साथ उन जीवों को भी प्रभावित करती है, जो इन पर निर्भर हैं। इस प्रकार पौधों की प्रजातियों में आने वाला बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करता है। ऐसे में यह भी तय होता है कि कौन सी प्रजातियां पनपती हैं और कौन सी घट सकती हैं।

## पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर असर

यह अध्ययन ईकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, अंकुरण का समय केवल एक प्रजाति ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। बीज के अंकुरण का समय यह निर्धारित करता है कि वह सूरज की रोशनी, जल और पोषक तत्वों के लिए कितनी बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कुछ पौधे बढ़ते तापमान के अनुरूप जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं और मौसम से पहले ही अंकुरित हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ प्रजातियां अपने सामान्य चक्र का पालन करती हैं। इससे शुरुआती अंकुरित पौधों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है और वे अन्य प्रजातियों पर हावी हो सकते हैं। इससे वनस्पति समुदाय में बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। पौधों के असमान विकास के कारण उत्पादन की स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है और अंततः उत्पादन घट जाता है।

## रक्षा सचिव की मौजूदगी में फाइनल हुआ सौदा

रक्षा मंत्रालय शक्ति सॉफ्टवेयर में अपग्रेड के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सौदा किया गया है। इन तीनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसमें उच्च विस्फोटक और क्षेत्र निषेध हथियार शामिल हैं। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मिली मंजूरी पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए मिली है। इस परियोजना को नागपुर की रॉकेट निमाता कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज और पूर्व आयुध निमाणी बोर्ड की कंपनी म्युनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के बीच विभाजित किया गया है। डीआरडीओ पहले से ही पिनाका रॉकेट के 120 किलोमीटर के मारक संस्करण को बनाने के उन्नत वर्णों में है और अगले वित्तीय वर्ष में इसका पहला परीक्षण किए जाने की उम्मीद है।

## 45 किलोमीटर है रॉकेटों की मारक कैपेसिटी

सीसीएस से मंजूरी मिलने वाले रॉकेटों की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान तथा चीन सीमा पर बहुत प्रभावी हो सकते हैं। सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पिनाका के लंबी दूरी के संस्करण तैयार होने के बाद सेना अन्य वैकल्पिक हथियारों की योजना छोड़ सकती है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पहले ही निर्यात क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है, क्योंकि इसे आर्मेनिया ने खरीद लिया है और फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं।













सरकार ने विहार में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जनवरी के है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे का विकास किया है। और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जनता इन उपलब्धियों से खुश है और और आगामी चुनाव में एनडीए को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। समेलन के अंत में एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुंथा सखाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को अपने बूथ पर मेहनत करनी होगी, मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना होगा और सरकार को जीतना होगा। एनडीए के नेताओं ने भी पूरे जोश के साथ कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे आगामी चुनाव में एनडीए को जीत सुनिश्चित करेंगे। समेलन में उपस्थित हर कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में रफिक अहमद की आवाज में एनडीए की जीत का श्वास जताया।





# कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

- यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फरस्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब,

समझे विरोधी बातों का अर्थ

- एक तरह तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

- आप नाश्ते में चपाती, पराठा, चिल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।
- लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खा या पी चुके हों। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ की हो और फिर चाय-टोस्ट, स्पाउटस या ड्राईफ्रूट्स आदि खाए हों। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सब्जियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

- सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।
- दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।



# लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है।
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन-बी12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस डाइट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहाँ जाने कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान.

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छाछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।



बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।



# चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेचैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है.

आपको क्या करना है ?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे.

पैर के तलुए में होते हैं सभी एक्जुप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्जुप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।



# शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं.

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाना।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिसाब से डाइट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



# आंखें में पानी आना

आंखें शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग है। सर्दी के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रैशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइ के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

गोला कपड़ा - आंखों को हाथों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आंखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हर्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिट चाय की पतियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सिकाई करें। ध्यान रहें कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखों में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में

चुटकीभर नमक डालकर आंखों की सिकाई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।

बैकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बैकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा।

डंडा दूध - कॉटन बॉल को ठंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों के आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को ठंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते हैं। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।

एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबेरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपको परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

कच्चा आलू - एस्ट्रिजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस ठंडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।



# मोहन के जापान दौरे से मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा



कम्पनी के निदेशक डाइकी अराई से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में चिकित्सा उपकरण निर्माण के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करा रही है। उन्होंने इस पार्क को भारत के तेजी से विकसित हो रहे हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बताया। उज्जैन में बन रहे मेडिकल डिवाइस और मुख्य रूप से मेडिकल सेक्टर के लिए भी जापान के उद्योगपतियों से निवेश की बात कही है। सीएम डॉ. यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश में मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग का नया हब बनने जा रहा है जिसके लिए जापान से निवेशकों के बड़े प्रस्ताव भी मिले हैं। उन्होंने सिस्मेक्स की अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस निर्माण तकनीक का अवलोकन किया और मध्यप्रदेश में सिस्मेक्स को आमंत्रित किया।

स्थापित करने में विशेष रुचि दिखाते हुए इसे वर्ष के अंत तक इसे शुरू करने की बात कही है। जापान की एण्डडी मेडिकल कम्पनी वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य निगरानी उत्पादों का उत्पादन करती है। डॉ. मोहन यादव ने कोबे और ओसाका में स्थित हेल्थ केयर और डॉयनोस्टिक कम्पनी साइसमेक्स प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों के उद्योगपतियों के साथ बैठक की और हेल्थ केयर, ऊर्जा और मैनुफेक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश एवं साझेदारी पर भी चर्चा की। उन्होंने जापानी कार निमाता कंपनी ह्योटोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर उनसे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।पैनासोनिक एनर्जी कंपनी लिमिटेड, डॉयनोस्टिक कंपनी साइसमेक्स सहित कई औद्योगिक कंपनियों ने बैटरी निर्माण और प्रदेश में ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई और एम्पी में भरपूर निवेश का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने जापान दौरे में प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने जो नींव तैयार की है उसका फायदा भारत की आने वाली

पीढ़ियों को मिलेगा।जापान की यात्रा डॉ.मोहन यादव के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। जापान में डॉ. यादव की सादगी लोगों के दिल में उतर गई। डॉ. यादव ने अपने सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। इस वीडियो में उनके सहज, सरल और आकर्षक व्यक्तित्व की विलक्षण छाप देखने को मिल रही है। लोग जापानी अंदाज और भाषा में उन्हें विदाई दे रहे हैं। इम्पीरियल होटल से चेक-आउट करते समय होटल के सदस्यों ने बड़ी देर तक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और तस्वीरें खिंचवाई। लोग तब तक होटल के मुख्य द्वार पर खड़े रहे, जब तक सीएम डॉ. यादव कार में नहीं बैठे। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 15,000 से अधिक निवेशकों के अलावा अन्य देशों के भी निवेशक इस समिट में भाग लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी। इस आयोजन से नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और राज्य की औद्योगिक छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद है। कहा जा सकता है कि डॉ.मोहन यादव का जापान दौरा एम्पी में जापानी कंपनियों के बीच निवेश को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है। उन्होंने अपनी चार दिन की जापान यात्रा में न केवल जापान के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की और निवेश और व्यापार के नए अवसरों को तराश बल्कि जापानी समाज और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। उन्होंने वहाँ की तकनीकी प्रगति, कला, संस्कृति और व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनी यात्रा के अनुभवों में समाहित किया। यह यात्रा मध्यप्रदेश और जापान के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी सहायक साबित हुई है।

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )  
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है )

## संपादकीय

### निर्वासन की समस्या

अंततः महिला, पुरुष और बच्चों सहित एक सौ चार अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान भारत पहुंच गया। अमेरिका में उचित दस्तावेज के बिना रहने वाले इन भारतीयों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लोग हैं। वैसे तो अमेरिका अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करता रहता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का भारत के लिए यह पहला निर्वासन है। इस संबंध में भारत और अमेरिका के बीच बात भी हो चुकी थी और ऐसा निर्वासन ट्रंप की चुनावी घोषणाओं में भी शामिल था। जहां कुछ अन्य देशों ने इस तरह के निर्वासन पर अपनी आपत्ति जताई वहां भारत ने इसे सहज स्वीकार किया है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र ऐसे अप्रवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अवैध तरीके से पहुंच कर न केवल उनके आर्थिक संसाधनों पर बोझ बनते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी संकट खड़ा करते हैं। अमेरिका सहित यूरोप के बहुत से देश इस तरह के अप्रवासन का संकट महसूस कर रहे हैं। स्वयं भारत भी अवैध घुसपैठियों की समस्या का सामना कर रहा है। यहां के राजनीतिक हलकों में हर दिन इसकी गूंज सुनाई देती है। इस समय भारत सरकार की नीति भी अवैध अप्रवासियों को रोकने की है जो पड़ोसी देशों से आकर बस गए हैं। भले ही इस पर कुछ समूह मानवाधिकार या नैतिकता का प्रश्न खड़ा करें लेकिन भारत के पास स्वयं अपनी स्थिति को देखते हुए इस निर्वासन को अमेरिकी शतरे के साथ स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे भारत की जिम्मेदारी यह भी बनती है कि वह दोहरी व्यवस्था को चाक-चौबंद करें। पहली यह कि उसके यहां अवैध अप्रवासन न हो और दूसरी यह कि यहां से अवैध ढंग से पलायन न हो। भारत एक और गंभीर समस्या से जूझ रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी अमेरिका, यूरोप के देशों में जाकर बसते हैं, जो या तो भारत विरोधी हैं, या आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं। ऐसे लोग भारत में प्रताड़ित होने का खतरे रचते हैं, और सहानुभूति के नाम पर वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिका और कनाडा से ऐसी घटनाएं उजागर हुई हैं जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को खतरे में डाला है। इसलिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले गिरोहों पर लगाम लगाए।

#### चितन-मनन

### मन की शक्ति

मन को जीवन का केंद्रबिंदु कहना असंभव नहीं है। मनुष्य की क्रियाओं, आचरणों का प्रारंभ मन से ही होता है। मन तरह-तरह के संकल्प, कल्पनाएं करता है। जिस ओर उसका रुझान हो जाता है उसी ओर मनुष्य की सारी गतिविधियां चल पड़ती है। जैसी कल्पना हो उसी के अनुरूप प्रयास-पुरुषार्थ एवं उसी के अनुसार फल सामने आने लगते हैं। मन जिधर रस लेने लगे उसमें लौकिक लाभ या हानि का बहुत महत्व नहीं रह जाता। प्रिय लगने वाले के लिए सब कुछ खो देने और बड़े से बड़े कष्ट सहने को भी मनुष्य सहज ही तैयार हो जाता है। मन यदि अच्छी दिशा में मुड़ जाए, आत्मबुधधर, आत्मनिर्माण और आत्मविकास में रुचि लेने लगे तो जीवन में एक चमत्कार हो सकता है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य भी महापुरुषों की श्रेणी में आसानी से पहुंच सकता है। सारी कठिनाई मन को अनुपयुक्त दिशा से उपयुक्त दिशा में मोड़ने की ही है। इस समस्या के हल होने पर मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य बनता हुआ देवत्व के लक्ष्य तक सुविधापूर्वक पहुंच सकता है। शरीर के प्रति कर्तव्य पालन करने की तरह मन के प्रति भी हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। कुविचारों और दुर्भावनाओं से मन गंद, मलिन और पतित होता है, अपनी सभी विशेषता और श्रेष्ठताओं को खो देता है। इस स्थिति से सतर्क रहने और बचने की आवश्यकता का अनुभव करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मन को सही दिशा देते रहने के लिए स्वाध्याय की वैसी ही आवश्यकता है जैसे शरीर को भोजन देने की। आत्मनिर्माण करने वाली जीवन की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने वाली उत्कृष्ट विचारधारा की पुस्तकें पूरे ध्यान, मनन और चिंतन के साथ पढ़ते रहना ही स्वाध्याय है। यदि सुलझे हुए विचारों के जीवन विद्या के ज्ञाता कोई संघात सज्जन उपलब्ध हो सकते हों तो उनका सत्संग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मन का स्वभाव बालक जैसा होता है, उमंग से भरकर वह कुछ न कुछ करना-खेलना चाहता है। यदि दिशा न दी जाए तो उसकी क्रियाशीलता तोंड़-फोंड़ एवं गाली-गलौज के रूप में भी सामने आ सकती है। मन में जब सद्बिचार भरे रहेंगे तो कुविचार भी कोई दूसरा रास्ता टटोलेंगे। रोटी और पानी जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा और परिपुष्टि के लिए आवश्यक हैं उसी प्रकार आत्मिक स्थिरता और प्रगति के लिए सद्बिचारों, सद्भावों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होनी ही चाहिए। युग निर्माण के लिए, आत्म निर्माण के लिए वह प्रधान साधन है। संकल्प की, मन की शुद्धि के लिए इसे ही दवा माना गया है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम 'दिल्ली में अवैध अप्रवासी, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण' है। 114 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का देश और विशेष कर राजधानी दिल्ली पर प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस का भी योगदान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश बांग्लादेशी घुसपैठिए 'फैमिली फस्ट' नीति अपनाते हैं। पहले परिवार का एक आदमी दिल्ली के भीतर आकर बस जाता है, पैसा कमाता है और रहने की जगह ढूंढता है। इसके बाद वह एक-एक कर पर परिवर्जनों को भी बांग्लादेश से लाना शुरू कर देता है। रिपोर्ट के अनुसार यह घुसपैठिए पहले कुछ दिन सीमाई राज्यों में रुकते हैं और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। बीते कुछ दिनों में अवैध महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली आने वाले 43 प्रतिशत से अधिक घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रुकते हैं। रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि वो घुसपैठिए, जो दिल्ली में 10 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, उनका नए घुसपैठियों को भारत लाने और यहाँ बसाने में अहम रोल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में इन घुसपैठियों को मदद करने में इनके खुद के कुछ समूह और मजहबी समूहों का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में बसने के बाद क्षेत्रीय या धार्मिक पहचानों के इर्द-गिर्द बनाए गए समूह इन्हें मदद करते हैं। इनमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल रहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में घुसपैठियों को सहायता देने और छत, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानूनी सहायता और यहाँ तक कि बैंकिंग तक पहुँच जैसी सेवाएँ देने बिना रजिस्टर किए गए एनजीओ और मजहबी समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी रूप से इमका दायरा सफ नहीं है। ये लोग अवैध प्रवासियों को रोजगार पाते और स्थानीय समुदायों में मिलने-घुलने में मदद करते हैं. कभी-कभी यह सरकारी नियम भी दरकिनार करते हैं। एनजीओ द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा, स्थानीय कई



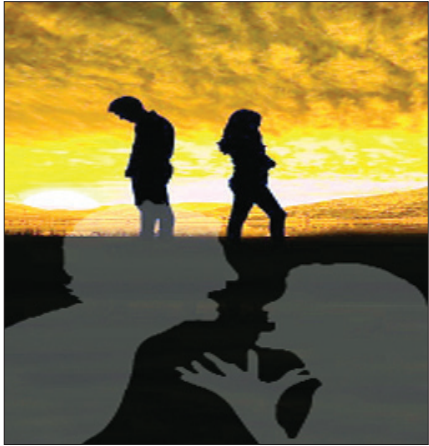
राजनीतिक हस्तियों की भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। यह अक्सर राजनीतिक चक्कादारी के बदले में अवैध प्रवासियों को सहायता देते हैं। ये राजनीतिक हस्तियाँ इन्हें घर ढूँढने के लिए फर्जी कागज तक दे सकती हैं। चुनाव के दौरान इन घुसपैठियों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि यह घुसपैठिए स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। इनमें से अधिकांश अकुशल क्षेत्रों में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घुसपैठिए दिल्ली में कम पैसों पर भी काम करने को राजी हैं। यह दिल्ली के भीतर निर्माण, घरेलू काम, सफाई और रेहड़ी जैसे कामों में जुड़े हैं। इससे दिल्ली के भीतर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यह लोग अपराध और गैर कानूनी धंधों में भी जुड़े हैं। यह दिल्ली की ब्लैक इकॉनमी को बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि यह घुसपैठिए सिर्फ भारत में कमा कर अपना ही काम नहीं चला रहे बल्कि पैसा

बांग्लादेश भी भेज रहे हैं। भारत में रहने वाले 80 प्रतिशत बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से कमाया हुआ पैसा वापस अपने घर भेजते हैं। लगभग 50 प्रतिशत बांग्लादेशियों ने भारत में खाते भी खुलवा लिए हैं। 20 प्रतिशत बांग्लादेशी घुसपैठिए जमीन भी खरीद चुके हैं जो चिंता की बात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में इस काम से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। यह भी सामने आया है कि दिल्ली में रहने वाले 96.3 प्रतिशत घुसपैठिए मुस्लिम हैं। इनके चलते दिल्ली के उन इलाकों की जनसांख्यिकी भी बदल गई है जहाँ यह आकर बसे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेशी घुसपैठिए सीलमुपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्ताफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी आदि जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बस जाते हैं। इनके चलते यहाँ रहने वाले निवासियों को मिलने वाली सुविधाओं पर दबाव पड़ता है।

## मुद्दा : रिश्तों में बढ़ती दरार चिंताजनक

की श्रेणी में नहीं आता। यह घटना हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और मानसिक अस्थिरता को दर्शाती है। रिश्तों में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह असहमति हिंसा का रूप ले लेती है, तो यह समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन जाती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर, ऐसा क्या हो गया है कि रिश्ते अब हिंसा और हत्या की ओर बढ़ रहे हैं। पति-पत्नी के बीच संबंधों को निजी मामला माना जाता है, लेकिन क्या इन संबंधों में मानवता और संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है? गुरुमूर्ति और माधवी के बीच झगड़े पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन इन झगड़ों ने हिंसा का ऐसा स्वरूप ले लिया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। जहां यह दंपति रहता था, वहां के पड़ोसियों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। यह समाज में बढ़ती एकाकी प्रवृत्ति और पड़ोसियों के बीच संवादहीनता को उजागर करता है। क्या हम इतने आत्मकेंद्रित हो चुके हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं? यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि समाज के लिए दण्ड भी है, जिसमें हमारी सामूहिक संवेदनहीनता साफ झलकती है। रिश्तों में विश्वास की कमी और संवादहीनता ऐसी घटनाओं की मुख्य वजह बन रही है। घरेलू हिंसा के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के

लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं के पीछे छिपे मानसिक और सामाजिक कारणों को समझना और उनका समाधान खोजना भी जरूरी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल पा रहे हैं। अगर किसी रिश्ते में समस्या है, तो उसका समाधान संवाद और परामर्श के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जब समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो वे हिंसा का रूप ले लेती हैं। हमें समझने की जरूरत है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करती है। माधवी की हत्या का मामला यह भी दर्शाता है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव को लेकर जागरूकता की कमी है। हमें समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हिंसक बना सकती हैं। इस दिशा में सामूहिक प्रयास की जरूरत है, जिसमें परिवार, समाज और सरकार की भूमिका अहम है। गुरु मूर्ति द्वारा किए गए इस अपराध को केवल एक अपराधों की मानसिक विकृति मान कर खारिज नहीं किया जा सकता। यह घटना समाज में व्याप्त गहरी समस्याओं की ओर इशारा करती है। इसे एक उदाहरण बना कर सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए न केवल सख्त कानूनों की जरूरत है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की भी महती आवश्यकता है।



यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रिश्तों में बढ़ती हिंसा और असंवेदनशीलता को रोकने के लिए हमें अपने मूल्यों और व्यवहारों पर पुनर्विचार करना होगा। यह समाज के लिए चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं जागें तो ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। गुरुमूर्ति और माधवी का मामला केवल एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि समाज के लिए आत्मचिंतन का विषय भी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर जोरदार प्रयास किए जाएं।



# Mirror mirror on the wall, who is oldest of us all

It is unusual for a political leader to proclaim an archaeological discovery, but it is hardly surprising in today's India. In another time, significant findings would be reported first in reputed academic journals, published after extensive peer review. For instance, the 1995 excavations of iron artefacts, furnaces and other materials dating to 1800 and 1000 BC in Uttar Pradesh were first reported in several Indian and foreign archaeology journals. It is a tedious process and may take years. But in the rich political pickings at the intersection of history and identity, time is short between elections and archaeology can no longer be left to archaeologists.

Recall former Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar driving the excavations in Rakhigarhi, one of the two biggest Harappan sites in India, and his government's push to find the mythical Saraswati river. Even Prime Minister Narendra Modi's priestly participation in the inauguration of the Ram temple at Ayodhya was the culmination of decades of BJP's involvement in the efforts to prove, including through archaeology, that the Babri Masjid was built at the site of a temple razed by Mughal emperor Babar.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin was only hewing to the national trend when, on January 24, he announced "with immense pride and unmatched satisfaction" that he was telling the world that "the Iron Age began on Tamil soil." Stalin backed his announcement with the results of two carbon dating tests and a third "luminescence" test. The tests, carried out by two reputed Indian institutes and a lab in the US, have established the antiquity of iron objects excavated from Mayiladumparai, Kilnamandi, Sivagalai and Adichanallur to the third and fourth millennia.

At the moment, the state's Archaeology Department has self-published the findings in a 73-page monograph. It has congratulatory endorsements by 10 high-profile archaeologists, including Rakesh Tiwari, former Director General of the Archaeological Survey of India (ASI), who found important UP Iron Age sites. If established conclusively through other independent assessments, including of methodologies, the Tamil Nadu findings would be a breakthrough development, one that challenges the neat categories of pre-history as we know them. As yet, no other known Iron Age site is dated earlier than 2000 BCE. The Tamil Nadu sites have been dated between 2953 BCE and 3345 BCE. The latest findings push the Iron Age to an antiquity of over 5,300 years and the use of smelting to about 4,000 years. With the establishment of the antiquity of the "Tamil landscape", as Stalin described it, it is inevitable that the DMK will claim bragging rights in matters of identity, pride and politics.

The findings come at the end of a decade of hyper-active archaeological work in Tamil Nadu, beginning with the excavations at Keezhadi in 2014. The period coincided with the start of Modi's prime-ministership, when Rakhigarhi and the hunt for Saraswati were high on the agenda of the BJP in its anxiety to link the Vedic age with the Harappan civilisation to establish the "Indic" origins of the first Hindus. The competitive archaeology meant that Keezhadi became embroiled right at the start in the conspiracy theory that the Centre was trying to stifle the discovery of a "Dravidian civilisation", especially after the ASI transferred the official in charge. The ASI, too, gave life to such theories by sitting on the Keezhadi report written by the official. The reasons are not known, but in Tamil Nadu, it is common knowledge that the report pushes the start of the Sangam Age back to 600 BCE instead of the widely accepted 300 BCE.

Public interest petitions have been filed in the court to get the ASI to publish the report. The high court intervened to get the ASI to hand over the site to the Tamil Nadu State Archaeology Department. The state government then conducted more excavations in Keezhadi and also set up a museum at the site. On the face of it, the Iron Age findings hold far more significance than Keezhadi.

# Budget leaves deregulation reforms on the back-burner

The Budget has left the task of deepening economic reforms unfinished in the critical areas of deregulation and ease-of-doing business.

The need to push urban consumption as well as to satisfy a large voter constituency seems to have been a major driver behind the 2025-26 Budget proposals. The unprecedented tax exemptions for incomes up to Rs 12 lakh annually comes as a bonanza for a middle class that had been carping for years over the excessive revenue burden on its shoulders. Yet, the government has managed to continue striding towards fiscal consolidation by bringing the fiscal deficit target down to 4.4 per cent from the 4.8 per cent achieved in FY 2025.

The other areas of revenue inflow are slated to be a much larger asset monetisation programme while the public sector disinvestment target is also ambitious despite having failed to meet goals set in the past few years.

Finance Minister Nirmala Sitharaman's eighth set of budget proposals has much more than just the big bang income tax relief, though it tends to overshadow the other elements. The leap to the Rs 12-lakh income level is bound to be controversial, given the arguments that taxes should be levied at levels close to a country's per capita income. Yet, with personal income tax confined to a small proportion of the population — roughly two per cent — it is unreasonable to expect this segment to bear such a large burden. hough indirect levies are borne by all citizens, direct tax collections are derived either from corporates or individuals, largely in the middle class category. In fact, personal income tax inflows are lately reported to be exceeding corporate tax revenues. So, this year's relief is an overdue concession. The presumption is this will revive urban consumption, which has been sluggish in the past year. The Economic Survey touched on the issue and called upon corporates to raise wages and compensation to boost demand. Tellingly, it commented on the fact that the industries are "swimming in profits" while salaries are not rising commensurately. In fact, increasingly, it seems private industry is putting all the onus on the state for economic development. For instance, industry associations had earlier called for higher public spending of up to 25 per cent in FY 2026. It stands to reason, however, that public capital expenditure cannot be increased ad infinitum. The Budget proposals envisage a 10 per cent rise in capex over the revised estimates of FY2025. This follows several years of double-digit increases in public spending. The state is rightly signaling that it is time for the private sector to play its due role in economic revival. Economic policymakers have spoken of the compact between government, private industry and workers that led to Japan's economic resurgence after the World War II. A similar compact may be difficult to evolve here, but there is no harm in giving it a shot.

Any industry-state cooperation can be facilitated by improving the ease-of-doing business. This Budget has unveiled several measures to unclog the regulatory cholesterol in the system. There is a flaw, however, in the very first step of setting up a high-level committee for



non-financial regulations. It has been given the prolonged deadline of one year. A group of determined experts can surely finalise recommendations within three to four months. Other measures are welcome, like the setting up of a mechanism under the Financial Stability and Development Council to formulate a framework to improve responsiveness.

The proposal for an Investment Friendliness Index for States, however, could be a competitive scorecard, but is not much of an incentive for reforms. The process of decriminalising laws is also being carried forward but a more rapid pace of change is needed.

As for specific schemes outlined in the proposals, there are three noteworthy ones. The first is the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana. It appears to be a well-designed model to help farmers in low productivity areas by easing credit and improving irrigation facilities, that can be gradually expanded to support more farmers. The second is the plan to augment tourism facilities at 50 locations in partnership with states. This sector has enormous potential for job creation and the proposals for skill development and provision of credit facilities are laudable. The third segment which is vital for this country is in the area of high technology. This includes a plan for a Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education as well as a new Fund of Funds for start-ups, which is being given an allocation of Rs 10,000 crore. It must be recalled that the earlier government contribution

of the same amount for the Fund of Funds led to commitments of as much as Rs 91,000 crore in the Alternate Investment Funds. All budgets are political documents and this one is no different. The largesse to the middle class comes days before the Delhi elections, an arena where the segment plays a big role. Several schemes announced for Bihar as well as unmistakable. They include the creation of a makhana board, new airports and irrigation projects.

The Budget has lost an opportunity, however, to make greater changes in the area of deregulation. The reforms in customs duty slabs are welcome as well as the cuts on levies on electronic component imports, especially for mobile phones and electric vehicles. But it is here that much greater overhauling is needed to reduce the effective duty rates. Simply put, tariff walls remain too high at a time when the external environment is dictating the need for greater opening up. Industry needs to plug into global supply chains while export growth is being threatened by the prospect of reciprocal levies by the US under an aggressive Donald Trump. The proposed income tax bill should come as a breath of fresh air, but a matching reworking of the customs duty framework is also needed. Finance Minister Nirmala Sitharaman's eighth Budget may bring good cheer to the middle class, but it has left the task of deepening economic reforms unfinished in the critical areas of deregulation and ease-of-doing business.

# Return of the natives

India must walk the talk on illegal migration

Days before Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington, a US military aircraft has brought 200-odd illegal Indian migrants back to their homeland. El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru — these are certainly not the countries that India, the world's fastest-growing major economy, would like to be bracketed with. Yet, here's the inescapable fact: India, that is Bharat, figures among the nations with the largest unauthorised immigrant population in the US, according to Pew Research Centre. A deportation flight may not seem to be the ideal build-up to the PM's visit, but New Delhi has managed to earn a few brownie points by talking tough on illegal immigration. During his recent trip to the US, External Affairs Minister S Jaishankar did some good diplomatic groundwork, reassuring the Trump administration that India was open to the 'legitimate return' of its errant nationals. India wisely avoided a confrontational approach, which would have created embarrassing bitterness ahead of



the Modi-Trump meeting. There was none of the bravado that had left Colombian President Gustavo Petro with egg on his face. He initially refused to accept military flights carrying deportees, but did a U-turn after President Trump threatened to impose tariffs and

sanctions on Colombia. Now, Petro is requesting migrants from his country to come home right away and "build social wealth". Such appeasement raises vital questions: Does India have a plan to rehabilitate around 18,000 nationals who have been identified for deportation from the US? And how will Delhi ensure that these people, including Punjabis and Gujaratis, do not undertake an immigration misadventure all over again?

A nationwide crackdown on unscrupulous travel agents is a must to deter desperate people who want to enter America by hook or by crook. The distant dream of Viksit Bharat can wait. The immediate priority should be to create lucrative job opportunities at home for skilled manpower. At the same time, streamlining legal migration ought to be high on the PM's agenda during his one-on-one with Trump.

# Miles to go on the nuclear front

High-sounding goals alone won't lead to power generation in the long run

The 2025-26 Budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman has certain supposedly 'big-ticket' ideas in the technology sector. These include the Nuclear Energy Mission, the Artificial Intelligence Mission and an increase in the allocation for the Ministry of Science and Technology to fund technology development and innovation in the private sector. She also announced a proposal for infrastructure expansion at the Indian Institutes of Technology and a multi-fold increase in the number of medical seats. All these are welcome ideas, though the timelines for their implementation and full financial implications are unclear. Most of them are not new and have been mentioned in previous Budget speeches. The Nuclear Energy Mission is meant specifically for research and development (R&D) pertaining to Small Modular Reactors (SMRs). The justification for going in for SMRs is the need for progressively reducing the dependence on fossil fuels. The goal, according to the FM, is "the development of at least 100 GW of nuclear energy by 2047". The minister said the mission would have an outlay of Rs 20,000 crore and at least five indigenously developed SMRs would be operationalised by 2033. However, she has not allocated funds for the new SMR mission in the Department of Atomic Energy's (DAE) budget, which remains stagnant compared to the previous year. It means Sitharaman's announcement on SMRs is only an intent.

The SMR intent, too, is not new. In her 2024 Budget speech, the minister had announced that India would go in for smaller nuclear reactors in a new push for nuclear energy; they were christened Bharat Small Reactors and Bharat Small Modular Reactors (BSMRs). In December 2024, the government told Parliament that R&D had been initiated to develop BSMRs and that "many countries have shown interest in collaborating with India" for this purpose. The deployment of these reactors will be in sectors with the need for captive

power generation, it was said. If the DAE has already initiated the development of SMRs, it should have been allotted funds in this year's Budget to pursue this work. The prefix 'Bharat' was dropped in Sitharaman's 2025 speech. Instead of the 'BSMR' used till December 2024, she has mentioned 'SMR' while referring to the new nuclear initiative. Small reactors and SMRs came on the policy radar when Niti Aayog published a paper on this subject in 2023. A 'small reactor' refers to a nuclear reactor (220 megawatts or MW) based on existing technology like pressurised heavy water reactors, while SMRs refer to even smaller reactors of 30-MW capacity onwards but with new designs. It is projected that such reactors could be pre-fabricated in factories and shipped to a site, reducing construction and installation time. Given their small size, such reactors would not need frequent refuelling, and could even be retrofitted in decommissioned thermal power plants. The safety, environmental and regulatory requirements for SMRs may be different from those for large reactors because SMR designs deploy passive systems and operate at low power and operating pressure. Globally, a handful of commercial SMRs are under development.

The development of nuclear energy was taken up soon after the country gained Independence. India has made substantial progress in developing indigenous capabilities and strategic output in the form of nuclear bombs. On the commercial electricity front, however, nuclear power has been lagging. Currently, India has 24 nuclear power reactors with a total installed capacity of 8,180 MW. Another 21 reactors with

capacity totalling 15,300 MW are at various stages of implementation. The DAE is known for fixing long-term targets for enhancing power generation from time to time. In the 1970s, when just a couple of nuclear power plants were functional, the DAE set a target of producing 10,000 MW by 1990. In the 1980s, the target was to achieve 20,000 MW by 2000. Then the deadline was changed to 2020. This year, the goal is 100,000 MW by 2047. Adding about 92,000 MW of nuclear energy in the next two decades is like chasing a mirage.



Nuclear energy is beset with problems of high capital expenditure, fuel supplies and massive environmental and safety costs. Take, for instance, the Gorakhpur nuclear plant in Fatehabad district of Haryana, with a planned capacity of four 700-MW units. The environmental assessment for the project was approved in December 2013, and the government okayed the first

phase in February 2014. The Atomic Energy Regulatory Board granted a siting licence in July 2015. Construction was due to begin in June 2015, with the first unit being scheduled to become operational by 2021. It was not until November 2020 that the pouring of the first nuclear safety-related concrete took place. In 2022, the completion deadline was revised to 2028, and now it appears that the first two units will be operational in 2032. The project is slated to cost Rs 40,000 crore. Anyone projecting nuclear power as an option for energy security should keep these ground realities in mind. In her speech, Sitharaman also spoke about 'active participation' of the private sector in achieving the ambitious target of producing 100,000 MW. For this, she said, the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act would be amended. Civil liability for nuclear accidents has been a sticking point for Indian private companies willing to participate in nuclear power production as well as foreign nuclear suppliers. The liability law passed in 2010 limits the third-party liability to Rs 1,500 crore and makes the plant operator responsible for it. If an accident occurs due to a faulty plant (as happened in Bhopal in 1984), the operator could take up the matter legally with the supplier. This clause in the liability rules has kept foreign suppliers away from the Indian market. In any case, civil liability is a serious matter and the government must rethink the cap if it has learnt any lesson from the Bhopal tragedy. High-sounding goals alone won't lead to power generation.



Rolls-Royce, Triveni Engineering to explore marine gas turbine ventures

New Delhi Triveni Engineering & Industries Ltd on Thursday said it has signed an initial pact with Rolls-Royce Marine North America Inc to explore opportunities in 4MW marine gas turbine generators.In a regulatory filing, Triveni Engineering & Industries said it has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Rolls-Royce Marine North America Inc to "explore opportunities to collaborate on programmes for 4 MW marine gas turbine generators (GTG) for customers in India."

"Rolls-Royce has a proven track record of powering some of the world's most advanced naval platforms, including the US Navy's DDG-51 destroyer," said John Shade, EVP for US Business Development and Future Programmes, Rolls-Royce Defence.Shade further noted that "India is a key strategic growth market for Rolls Royce and we are confident that our industry-leading marine gas turbine generators are an ideal choice to power the Indian Navy's future fleet." This would include several key areas including design, development and manufacturing of the marine GTGs, as well as comprehensive sales and support activities.Abhishek Singh, SVP of Business Development and Future Programmes for India and Southeast Asia, Rolls-Royce, said the MoU is significant, given the potential to establish end-to-end support for our marine gas turbine generator in India, from installation and testing to after-market support.Tarun Sawhney, Vice Chairman & Managing Director, Triveni Engineering & Industries Ltd said "such a partnership can not only help us bring advanced technology to power India's naval defence requirements, but also help enhance the capability of indigenous naval defence ecosystem in the country," he said.

Once dismissive of cheaper AI from India, Altman now says it can lead a revolution

NEW DELHI. Some may see it as a sobering effect of the onslaught of China's cost-beltng DeepSeek in the global world of AI, but OpenAI founder Sam Altman - who just a year and a half ago dubbed India's ambitions of building foundation AI models with limited budget as a "hopeless" pursuit - now believes the country can be "one of the leaders" in heralding technological leapfrogging.Asked about his 2023 comment (made at a specially curated event organised by The Times of India), Altman - back in the Asian region following the DeepSeek launch at a fraction of cost compared to what OpenAI and others such as Meta, Google and Microsoft are spending - was more measured in his response, while emphasising that he was "quoted out of context". "I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's really quite amazing to see what the country has done in embracing technology and building the entire stack," he said during a fireside chat with IT & electronics minister Ashwini Vaishnaw.

"India is an incredibly important market for AI in general, (and) for OpenAI in particular. It's our second biggest market. We tripled our users here last year."He said India has a high degree of creativity, and should be a "leader" when it comes to developing reasoning models at efficient costs.

Ashwini Vaishnaw - while talking about the work under the India AI Mission and the need for developing local foundation models keeping India's context, languages, cultural and regional nuances in mind - said the country has the capability to do cutting-edge work but at a fraction of costs being incurred by US companies.

"Our young entrepreneurs, our startups, our researchers, they are really, really focused on getting to that next level of innovation which will reduce the cost. Our country sent a mission to the Moon at a fraction of the cost that many other countries spent. Right. Why can't we do a (AI) model which will be a fraction of the cost that many other countries do? So yes, innovation will bring that cost down. We think that kind of thing will come out in this process," the minister said to an audience that included startup founders and those engaged in the field of AI.

Gold Prices Cool After Hitting All-Time High: Will It Resume Surge Know Rates In Your City

New Delhi. After touching all-time high levels, gold prices in India have cooled a bit and opened at Rs 84,460 per 10 grams on the MCX. However, resuming the rally, the gold rate rose to Rs 84,635 per 10 grams in the early trade as of 9:54 am. Silver, on the other hand, was trading lower by 0.36 per cent at Rs 95,620 per kg.

The gold rate had hit its all-time high of 85,210 per 10 grams in the previous session on Wednesday, amid weakness in the rupee and profit-taking in the dollar index.Rahul Kalantri, vice-president (commodities) of Mehta Equities Ltd, said, "Gold and silver showed very high price volatility and gold prices hit \$2,900 per troy ounce levels in the international markets for the first time. Gold prices also hit record highs in the domestic markets amid weakness in the rupee and profit-taking in the dollar index."The dollar index slipped below 108 marks and supported gold and silver prices, he added."However, an increase in the ADP non-farm employment to 1,83,000 limits gains of precious metals," Kalantri added.On the silver prices, he said its prices plunged after upbeat US ADP non-farm payroll data but safe-haven buying is supporting bullion prices.Will Gold Rate Resume Upside Movement?"Gold and silver could hold its key support levels of \$2,770 and \$31.40 per troy ounce, respectively, on a weekly closing basis in the international markets. Gold has support at \$2,851-2,838 while resistance at \$2,897-2,912. Silver has support at \$31.98-31.78 while resistance is at \$32.45-32.64," Kalantri said.

Nissan Motor seeking new partners as deal with Honda set to collapse

Nissan's Board Is Pushing Chief Executive Officer Makoto Uchida And Other Executives To Develop A More Comprehensive Restructuring Plan. Image: Bloomberg

New Delhi Nissan Motor Co. is seeking out a new partner as it prepares to end negotiations to form a joint holding company with Honda Motor Co., people familiar with the matter said.

The Japanese carmaker is looking for a partner that would ideally be from the technology sector and US-based, said the people, who asked not to be identified because the information isn't public.

North America is Nissan's most important market and the wider shift toward

electrification and automation has pushed global carmakers to seek out alliances with other industries. Nissan shares jumped as much as 8.7 per cent in early afternoon trading in Tokyo on Thursday.

Shiro Nagai, a Nissan spokesperson, declined to comment, adding that any details concerning talks with Honda would be announced as planned around mid-February.

The carmakers confirmed yesterday that they are still discussing various options, including the possibility of ending deal talks. Honda had floated the idea of acquiring Nissan and making it a subsidiary, which met with strong opposition within Nissan, one of the people said. The level of investment was also a sticking point, the person added.

Honda had also made the restructuring of Nissan's operations a prerequisite for any transaction to materialize. Yet, apart from reducing jobs and output, Nissan's current plans do not include any plant

closures. Ending discussions with Honda, which were exclusive, would let either side walk away from the deal without having to pay a hefty cancellation fee of ¥100 billion (\$657 million), according to their memorandum of understanding on Dec. 23.

Nissan's board is pushing Chief Executive Officer Makoto Uchida and other executives to develop a more comprehensive restructuring plan in parallel to any discussions with any potential new partner, the people said.

The goal is to come up with a deeper revamp in time for Feb. 13, when the maker of Altimas and Pathfinders is scheduled to report quarterly results.

That's also when the board will meet to formalize its decision, one person said.

Nissan has struggled to regain its footing since the 2018 arrest and purge of former Chairman Carlos Ghosn on charges of underreporting compensation, leaving it with an outdated product lineup and too much production capacity.

The scope of Nissan's financial crisis became obvious in November, when a 94 per cent drop in net income triggered plans to cut 9,000 jobs, lower production capacity by 20 per cent and slash its annual profit guidance by 70 per cent.

Any new restructuring plans would go beyond those figures. "Further earnings deterioration is possible at Nissan," said Citigroup Inc. analyst Arifumi Yoshida.

"Additional restructuring measures are vital." Hon Hai Precision Industry Co., the maker of iPhones known as Foxconn that is trying to establish a foothold in outsourced manufacturing of electric vehicles, put its interest in pursuing Nissan on hold last year when it became clear that the Japanese automaker was in negotiations for a potential combination with Honda.

But the electronics contract manufacturer didn't give up completely, preferring to see if the two would make legitimate progress toward a deal before deciding on its next move.

Sensex, Nifty fall after flat opening as investors await RBI rate decision

NEW DELHI. Benchmark stock market indices fell after opening flat on Thursday as investors wait for the Reserve Bank of India's rate decision on Friday.The S&P BSE Sensex was down 151.58 points to 78,119.70 at 10:12 am, while the NSE Nifty50 traded 42.95 points lower at 23,696.30.

Most of the other broader market indices were also trading flat or in the red as volatility gained momentum.

Some pharma and IT stocks were among the gainers, but bank and financial services stocks were down.

The top five gainers on the Nifty50 were BPCL, ITC Hotels, Cipla, Dr Reddy's and Power Grid. On the other hand, the top losers were Trent, Titan, Ultratech Cement, M&M and Eicher Motors.

While the mood on Dalal Street remains volatile, there are wide expectations that the RBI will cut

interest rates for the first time in nearly 5 years. A 25 bps rate cut is expected.

Dr VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial



Services, said "The market is moving into a consolidation phase on expectations of a pickup in growth in the coming quarters. In the near-term the market is likely to get a mild boost from a possible 25 bp rate cut by the

MPC tomorrow."If the RBI's Monetary Policy Committee (MPC) does cut rates, it will be another boost to consumption after Finance Minister Nirmala Sitharaman announced fresh income tax benefits in Budget 2025.

"Even though steadily depreciating INR doesn't provide a favourable macro backdrop for a rate cut, the MPC is likely to go for a 25 bp cut tomorrow to keep the optimistic momentum provided by the Budget going," he added.

Prashanth Tapse, Senior VP (Research), Mehta Equities Ltd, said, "All eyes are on Friday's RBI MPC decision, with hopes for a rate cut to boost consumption."

Tapse also said that key corporate earnings from companies such as Bharti Airtel, SBI and ITC will also determine the mood of investors on Dalal Street.

Korean carmaker Kia under government lens in tax evasion case

NEW DELHI. After Volkswagen, South Korean automaker Kia has come under Indian authority's lens for evading taxes.As per the government, Kia has evaded \$155 million in taxes by misclassifying component imports, saying that authorities found Kia's Carnival car model was being imported in parts or components in separate lots via different ports, with the "intent to discharge lesser customs duty".

Kia India said it remains committed to following regulatory requirements, stating that they have consistently cooperated with the authorities whenever required.

"Regarding the current matter, we have filed a detailed response, supported by evidence and documentation to substantiate our stand. However, as the issue is currently under consideration of the relevant authorities, we won't be able to comment further or provide additional details on the matter as of now," said Kia India.A 432-page notice, accessed by Reuters, states Kia imported Carnival car parts separately through multiple ports to lower



Assam women participation high in stock market investment

A statement jointly issued by the National Stock Exchange of India Limited and National Securities Depository Limited revealed that women make up 29.8 per cent of the state's 24.6 lakh registered investors

GUWAHATI. Assam has the fifth highest female participation among all states in India's investment landscape, with women making up 29.8 per cent of the state's 24.6 lakh registered investors. This was revealed in a statement jointly issued by the National



Stock Exchange of India Limited and National Securities Depository Limited stated.To promote investor awareness and protect investors' interests in the security market, the two institutions organised a Mega RISA (Regional Investor Seminar for Awareness) here on Wednesday under the aegis of Securities and Exchange Board of India (SEBI) along with other market infrastructure institutions.

SEBI General Manager Aradhana Verma graced the programme as chief guest.Titled "Viksit Bharat ka Viksit Niveshak", the event focused on educating investors about the securities markets, fraud and scam prevention,

rights and responsibilities and smart investing practices.The Mega RISA provided a comprehensive perspective on investor rights, responsibilities, emerging market trends, with insightful discussions on fraud prevention in the digital era, financial literacy, and smart investment practices.

The event included panel discussions on "The Future of Securities Market – Trends, Challenges and Opportunities", and "Let's Deep Dive into DEMAT".

Experts from SEBI and financial institutions highlighted key issues such as emerging market trends, demat-related issues, cyber threats and unregulated investment risks.

Participants were also educated on safe investing practices and identifying red flags in Ponzi schemes, unauthorised advisors, digital scams etc.

Additionally, the event included a financial quiz and a "Nukkad Natak", making financial education accessible and engaging.The organisers of the event said the overwhelming participation of investors.

Will RBI cut key rates for 1st time in 5 years 4 things you need to know

New Delhi. The Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) is set to announce its policy decision on Friday, under the leadership of newly appointed Governor Sanjay Malhotra.

There are expectations that the central bank's MPC will decide on cutting the key rates for the first time in 5 years by 25 basis points (BPS).

The last time the MPC announced a rate cut was way back in May 2020.

While analysts have mixed views on whether the RBI will cut the repo rate, a positive announcement could provide another boost to consumption after the recent tax cuts in the Union Budget 2025.

So, will the RBI's MPC cut rates tomorrow or stay focused on keeping inflation under control? Here are 4 things you need to know:

**25 BPS RATE CUT LIKELY**

A 25 basis points (bps) rate cut is widely anticipated, marking the first reduction since the Covid-19 pandemic in May 2020.

The repo rate has remained steady at 6.5% since February 2023, following a cumulative 250 bps hike between May 2022 and February 2023.

Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services, believes that a cut is likely despite concerns over the depreciating rupee.

"The market is



moving into a consolidation phase on expectations of a pickup in growth in the coming quarters.

In the near term, the market is likely to get a mild boost from a possible 25 bps rate cut by the MPC tomorrow.

Even though steadily depreciating INR doesn't provide a favourable macro backdrop for a rate cut, the MPC is likely to go for a 25 bps cut tomorrow to keep the optimistic momentum provided by the Budget going," he said.

Madan Sabnavis, Chief Economist at Bank of Baroda, also supports the likelihood of a rate cut.

"The budget has provided growth stimulus, and inflation is expected to ease. However, the rupee remains under pressure due to global trade uncertainties," he noted.

On the other hand, Rumki Majumdar, economist at Deloitte, expects the RBI to

maintain a cautious approach.

"Balancing inflation and credit growth is tricky. While there is pressure to cut rates, the RBI may choose to keep rates unchanged but maintain an easy policy stance," she said.

Umeshkumar Mehta, CIO at SAMCO Mutual Fund, highlighted global factors influencing the RBI's decision.

"Bond yields in the US are rising due to inflation concerns, putting pressure on the Indian rupee. To avoid further depreciation, the RBI may choose to keep rates unchanged," he said.

**NEUTRAL STANCE TO CONTINUE**

The government's fiscal approach in the Union Budget 2025 has provided room for a potential rate cut to stimulate growth.

India's GDP growth slowed to a seven-quarter low of 5.4% in Q2 FY25, adding pressure on the central bank to support economic expansion.

According to Bajaj Broking Research, the MPC is expected to maintain its neutral stance, allowing flexibility in future policy decisions.

The brokerage also noted that RBI's recent liquidity measures aim to stabilize the financial system, reinforcing expectations of monetary easing.

Edelweiss Mutual Fund predicts a total rate cut of 50 bps in the first half of 2025, emphasizing the need for monetary policy to complement

fiscal measures in boosting demand.

**INFLATION AND RUPEE PROBLEM**

Inflation remains a key factor in the RBI's decision-making.

Consumer Price Index (CPI) inflation for FY26 is projected at 4%, with January inflation expected to be below 4.5%.

December inflation stood at 5.22%, marking four consecutive months above 5%, while food inflation eased to 8.4% from 9% in November.

Despite easing inflation, concerns over currency stability persist.

The rupee has been under pressure due to rising US bond yields and global trade tensions.

A rate cut could further weaken the currency, prompting the RBI to adopt a wait-and-watch approach.

**POSSIBLE IMPACT ON STOCK AND BOND MARKETS**

The stock and bond markets are expected to react sharply to the RBI's decision.

A rate cut could benefit banking stocks and lower borrowing costs for businesses and individuals, boosting consumption.

However, if rates remain unchanged, volatility may rise as investors recalibrate their expectations.

Prashanth Tapse, Senior VP (Research) at Mehta Equities Ltd, highlighted the dual factors influencing market sentiment.



## Legs chained, handcuffed on flight to India from US, claim deportees

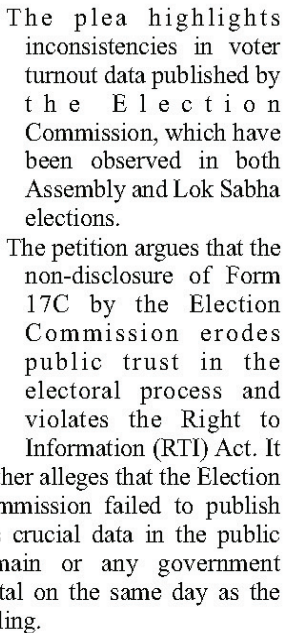
**The Donald Trump administration in the US deported 104 illegal Indian immigrants, including 19 women and 13 minors, who arrived in Amritsar on Wednesday.**

**New Delhi.** In a bid to maintain transparency in electoral process, senior Congress leaders have filed a petition in the Supreme Court, demanding that the Election Commission of India (ECI) be directed to upload Form 17C on its website immediately after polling ends. Form 17C contains detailed information on the number of votes cast at a polling station. The public interest litigation (PIL) also requests an interim order, urging Supreme Court to direct the central poll body to upload Form 17C for the Delhi Assembly Elections 2025 and all upcoming elections with immediate effect. The PIL has been submitted on behalf of Amethi Congress MP

Kishori Lal Sharma and Congress spokesperson Alok Sharma.

The petition states that to ensure the public availability of Form 17C, the Election Commission should be directed to upload it immediately on its website. This, according to the plea, will enhance transparency in the election process and help prevent electoral malpractices.

Form 17 C refers to all the data given to polling agents on election day, including number of voters in each polling station, number of registered voters in an area, number of voters who didn't vote, names of candidates and the voters.



**New Delhi.** The Indian nationals who were deported from the US for illegally arriving in the country claimed that they were sent back on a military aircraft with their hands and legs cuffed throughout the journey.

A US military aircraft carrying 104 deportees, including 19 women and 13 minors, landed at Amritsar airport on Wednesday amid Donald Trump's crackdown on illegal immigrants.

One of the deportees, Jaspal Singh, a 36-year-old man from Punjab's Gurdaspur, said that they were unshackled only after landing in Amritsar.

"We thought we were being taken to another camp. Then a police officer told us that we were being taken to India. We were handcuffed, and our legs were chained. These were opened at Amritsar airport," he told news agency PTI. Singh added that he was kept in custody in the US for 11 days before being sent back home. However, earlier on Wednesday, the government fact-checked a photo, which was widely shared on social media with the claim that Indian migrants were handcuffed and their legs were chained during deportation, saying it was actually of Guatemalan nationals, not Indians.

"I had asked the agent to send me with a proper visa, but he deceived me," said Jaspal, adding that the deal was made for Rs 30 lakh. "A huge sum was spent. The money was borrowed."

Harwinder Singh, another deportee from Punjab, said he was taken through Qatar, Brazil, Peru, Colombia, Panama, and Nicaragua before reaching Mexico. While travelling from Mexico to the US, "We crossed hills. A boat that was carrying me along with other people was about to capsiz[e] in the sea, but we survived," he said.

**NEW DELHI.** Purvanchali voters, who favoured the ruling AAP in the last two assembly elections, appear divided between the AAP and the BJP this time. In most Purvanchali-dominated assembly segments, the people have keenly assessed which party performed better before casting their votes.

The election campaign saw the three main parties, including the Congress, outdo one another to woo the Purvanchali vote. This segment, mainly from Bihar, Eastern UP, Uttarakhand and Jharkhand, plays a crucial role government formation in the national capital.

An estimated 25% of the 40 lakh-odd registered voters have Purvanchali backgrounds. Besides Dalits and Muslims, powerful vote banks in the city, this section stands out as a formidable influencer of the voting outcome. It is reported that they can influence results in 25-27 assembly constituencies in the city. They are in the majority in nearly 12 assembly seats, and parties have given tickets to Purvanchali candidates on many.

Ganesh Prasad Sinha, a Purvanchali from Patna, said ongoing politics over developmental issues upset him. He said that governance should be the core of any political party and that the common man's problems should get priority. The octogenarian voter said that facilities made for senior citizens, like pension, railway fare concession, etc., should neither be on hold nor discontinued. Another Purvanchali voter, Shahabuddin from the Seelampur assembly constituency, discussed the voters' limited choices. "The area is thoroughly neglected by both parties ruling in the state and the Centre.

Many who voted for the Congress in Sheila Dikshit's time preferred AAP in later elections. They might have been willing to vote for the grand old party but hesitated, lest their vote might go to waste. The only option for them was the ruling party for them." Bibha Jha, a voter in the Laxmi Nagar constituency, claimed voters remained equally divided between AAP and BJP.

**New Delhi.** India will launch the Chandrayaan-4 mission to bring back samples of moon rocks to the Earth in 2027, Science and Technology Minister Jitendra Singh said. Chandrayaan-4 will involve at least two separate launches of the heavy-lift LVM-3 rocket that will carry five different components of the mission which will be assembled in orbit.

"The Chandrayaan-4 mission aims to collect samples from the moon's surface and bring them back to the Earth," Mr Singh told PTI Videos in an interview.

The minister said the Gaganyaan mission, which involves sending Indian astronauts in a specially designed spacecraft to low-earth orbit and bringing them back safely, will be launched next year. In 2026, India will also launch Samudrayaan, which will take three scientists in a submersible up to a depth of 6,000 metres in the deep ocean, to explore the seabed.

"This achievement will align with the timelines of India's other landmark missions, including the Gaganyaan space mission, marking a pleasant coincidence in the nation's journey toward scientific excellence," Mr Singh said. Mr Singh said Prime Minister Narendra Modi highlighted the Samudrayaan mission in his Independence Day speech.

The minister underscored the potential of the Samudrayaan to unlock vast resources, including critical minerals, rare metals, and undiscovered marine biodiversity, all of which are crucial for the country's economic growth and environmental sustainability.

The first uncrewed mission of the Gaganyaan project, carrying a robot, 'Vyommitra', will also take place this year. Mr Singh said that while the Indian Space Research Organisation (ISRO) was established in 1969, it took more than two decades to set up the first launch pad in 1993.

The second launch pad came up in 2004, another decade-long gap. However, in the last 10 years, India's space sector has undergone unprecedented expansion, both in terms of infrastructure and investment, he said.

"We are now building a third launch pad and for the first time for heavier rockets, and expanding also beyond Sriharikota with a new launch site in Tamil Nadu's Tuticorin district to launch small satellites," Mr Singh said. The minister said that India's space economy, currently valued at USD 8 billion, is projected to reach USD 44 billion in the next decade, further cementing India's role as a global space powerhouse.

**New Delhi.** The Centre is "seriously considering" enacting a new law to establish a framework which will promote "safe, orderly and regular migration for overseas employment". This move comes amid a row over the United States deporting over a hundred Indian migrants who landed in Amritsar yesterday on a C-17 US military aircraft, chained and shackled.

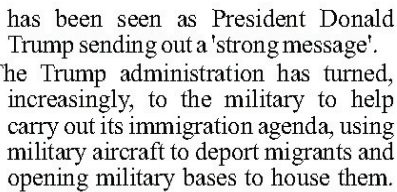
The tentatively titled 'Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2024' emerged from a report presented in Lok Sabha by the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, headed by Congress MP Shashi Tharoor, on Monday. The migrants, 104 in total and hailing from various states, were rounded up in a sweeping crackdown on illegal immigration in the U.S. Among them, 33 were from Haryana and Gujarat, 30 from Punjab, three from Maharashtra and Uttar Pradesh, and two from Chandigarh. Nineteen women and 13 minors, including a four-year-old boy and two girls aged five and seven, were also on the flight.

"The government carefully monitors the number of students in all foreign countries, and carefully monitors their welfare in situations of tension. We alert students, as we have done in Ukraine. Whenever there is a situation when we need to run flights, we are prepared. We have contingency plans," said External Affairs Minister S Jaishankar in Parliament today.

Mr Tharoor acknowledged that deportations of illegal immigrants are routine but criticised the US authorities for the manner in which they handled the Indian nationals. India Considering New Law For Migrants' Safety Amid US Deportation Row This move comes amid a row over the United States deporting over a hundred Indian migrants who landed in Amritsar yesterday on a C-17 US military aircraft, chained and shackled.

**New Delhi.** Opposition MPs targeted the government Thursday over the United States' deportation of 104 illegal Indian immigrants, demanding a discussion in Parliament over their "inhuman" treatment, which included shackling arms and legs while on a US military aircraft that reached Amritsar last night.

illegal immigrants, who were not handcuffed. The use of military aircraft



**New Delhi.** Several families are facing financial uncertainties after their kin were sent back to India, barely a week after the new United States President Donald Trump signed an executive order to deport all illegal migrants back to their respective countries.

Akashdeep Singh and Akash, hailing from Punjab and Haryana respectively, were among 104 illegal Indian migrants who landed in Amritsar on February 5 after being deported from the US.

Akashdeep's father claimed that they had spent over Rs 60 lakh to secure a bright future for their son. Belonging from Rajatal, a village near India-Pakistan border, Akashdeep was caught by US authorities on January 23.

Akashdeep spent seven months in Dubai before going to the US with the help of an agent. He had called his father on Wednesday after landing in

**Akashdeep's father claimed that they had spent over Rs 60 lakh to secure a bright future for their son, while 20-year-old Akash's brother Subham sold off 2.5 acres of their land in Haryana's Karnal to pay Rs 65 lakh to an agent.**

India, assuring him that he was safe.

However, his family said that they were facing severe financial stress as they were struggling to recover from the massive debt that they incurred while sending their son abroad.

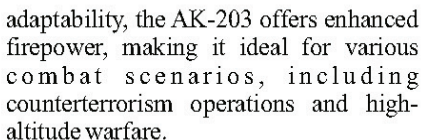
Akashdeep's father, Swaran Singh, revealed that they mortgaged their land, took loans and even sold their jewellery and cattle to finance his trip. "We spent over Rs 60 lakh to send him to the US. We took loans and pledged

**With superior ergonomics, durability, and adaptability, the AK-203 delivers enhanced firepower, making it ideal for diverse combat scenarios, from counterterrorism operations to high-altitude warfare.**

**NEW DELHI.** The Indian Army is set to receive 70,000 AK-203 assault rifles in 2025, followed by an additional one lakh units in 2026 under an arms deal with Russia, according to defence sources.

This delivery, part of a larger agreement with Moscow, aims to equip Indian soldiers with one of the most advanced and reliable assault rifles in the world. The Indian Army has already received 35,000 of these rifles in 2024. The AK-203, manufactured under a joint Indo-Russian venture in Amethi, Uttar Pradesh, is replacing the ageing INSAS (Indian Small Arms System) rifles currently in service. Indigenous components in these AK-203 rifles will be increased to up to 30 per cent this year, with further enhancements in subsequent supplies, according to Army officials.

With improved ergonomics, durability, and



a modernised version of the legendary Kalashnikov series, the AK-203 provides superior accuracy, a lightweight construction, and compatibility with advanced optics and accessories. The rifle

is chambered for 7.62—39mm ammunition, which offers greater stopping power compared to the 5.56mm INSAS. This procurement aligns with India's broader defence indigenisation goals under the 'Make in India' initiative, ensuring that most of the rifles are manufactured domestically by Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), according to Defence Ministry officials. This not only enhances India's self-reliance in arms production but also strengthens bilateral defence cooperation with Russia. The AK-203 contract, signed in July 2021 and valued at over â,15,000 crore, is an agreement between India and Russia for the domestic production of AK-203 assault rifles. It involves a joint venture between Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) and Rosoboronexport (RoE) for the production of over 6.1 lakh

AK-203 rifles, including technology transfer from Russia. The first batch of 70,000 AK-203 rifles was reportedly delivered to the Indian Army on January 25, 2022, though the date has not been officially confirmed. Licensed production of the rifles officially commenced in January 2023. Between May and July 2024, another batch of 35,000 rifles was delivered, marking a significant step in the indigenous manufacturing and supply of these advanced assault rifles to the Indian armed forces.

With ongoing tensions along the Line of Actual Control (LAC) with China and persistent cross-border threats from Pakistan, upgrading infantry weapons has been a priority for the Indian Army. The AK-203 provides troops with a more robust, easy-to-maintain, and combat-proven firearm, significantly enhancing their operational readiness.



NEWS BOX

Elon Musk Changes X Bio, Mentions White House Role. It's Not DOGE Boss

World Tesla chief Elon Musk, who heads the US Department of Government Efficiency in the Trump administration, has updated his profile bio on X (formerly Twitter). It now reads "White House Tech Support".Musk, who has been considerably active on X since acquiring it and often shares memes, had changed his bio to CTO (Chief Troll Officer) last year.After Trump's inaugural ceremony on January 20, the White House had announced that the United States Digital Service - which was created by former president Barack Obama - would be publicly renamed the United States DOGE Service (USDS). It was established in the Executive Office of the President.Confirming this yesterday, Elon Musk said the USDS was renamed to DOGE Services to modernise computer systems in the US government. Following this, the "tech support" bit appeared in his bio.Musk, A Dedicated DOGE Leader

Earlier this week, on February 2, Musk said "DOGE is working 120 hours a week", drawing flak on social media. Before that, Musk was reportedly sleeping at the DOGE headquarters in Washington D.C., as per WIRED.Musk was reportedly eyeing his office inside the Oval Office, West Wing of the White House. However, US President Donald Trump clarified that a separate office has been set up for Musk and his team. And it is not a part of the Oval Office.During a press briefing on Saturday (January 25), when Trump was asked if Musk has an office in the West Wing, the President categorically said, "No, no, not - it's not Elon's office.""We have an office that's set up for purposes of - when I do an executive order, that the order is carried out, not that it sits around for three months. And we'll have about 20 people, maybe more, working out of that office," Trump said.DOGЕ was formed to "dismantle government bureaucracy, slash excess regulations, cut wasteful expenditures, and restructure federal agencies - essential to the 'Save America' Movement."Trump and Musk have claimed that \$2 trillion could potentially be saved, but most experts believe that is not realistic without deep cuts to crucial social services or benefits.

South Korea Ministries Block Access To China's DeepSeek On Work Computers

Seoul, South Korea.South Korea's defence and trade ministries said Thursday they had blocked DeepSeek's access to work computers, following a request from the country's data watchdog for the Chinese AI startup to clarify how it manages user information. DeepSeek launched its R1 chatbot last month, claiming it matches the capacity of artificial intelligence pace-setters in the United States for a fraction of the investment.South Korea, along with countries such as France and Italy, have asked questions about DeepSeek's data practices,



submitting a written request for information about how the company handles user information.Seoul's defence ministry said Thursday it had blocked DeepSeek from military computers connected to the internet, while the trade ministry said that access had been temporarily restricted on all PCs within the agency."Blocking measures for DeepSeek have been implemented specifically for military work-related PCs with Internet," a ministry official told AFP. The trade ministry said DeepSeek has not responded to the data watchdog's inquiry."We have temporarily blocked DeepSeek since it has not responded to The Personal Information Protection Commission's inquiry," a trade ministry official told AFP.

Marco Rubio Says Trump Meant Only Temporary Gaza Move For Rebuilding

Washington.US President Donald Trump only wants Palestinians to leave Gaza temporarily while the territory is reconstructed, Secretary of State Marco Rubio said Wednesday.Trump stunned the world and drew condemnation when he proposed Tuesday at a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that the United States could take over war-battered Gaza.Trump's idea "was not meant as hostile. It was meant as, I think, a very generous move -- the offer to rebuild and to be in charge of the



rebuilding," Rubio told reporters on a visit to Guatemala.Trump offered a US "willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions," Rubio said."And in the meantime, the people living there will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris," he sai.

Rahim Al-Hussaini is named the new Aga Khan, spiritual leader of Ismaili Muslims

The Aga Khan is considered by his followers to be a direct descendant of the Prophet Muhammad and is treated as a head of state.

LISBON. Rahim Al-Hussaini was named Wednesday as the new Aga Khan, spiritual leader of the world's millions of Ismaili Muslims, following the death of his father. The 53-year-old was designated as the Aga Khan V, the 50th hereditary imam of the Ismaili Muslims, in his father's will. His father died Tuesday in Portugal.The Aga Khan is considered by his followers to be a direct descendant of the Prophet Muhammad and is treated as a head of state.The Aga Khan Development Network and the Ismaili religious community announced earlier that His Highness Prince Karim Al-Hussaini, the Aga Khan IV and 49th hereditary imam of the Shiite Ismaili Muslims, died surrounded by his family. Prince Rahim is the eldest son of the former Aga Khan. He was educated in the U.S., having studied comparative literature at Brown University, and has served on the boards of various agencies within the Aga Khan Development Network, the spiritual

leader's main philanthropic organization, according to a statement it released Wednesday.The organization deals mainly with issues of health care, housing, education and rural economic development. It says it works in over 30 countries and has an annual budget of about \$1 billion for nonprofit development activities.The Aga Khan Development Network said Prince Rahim took a special interest in its work to fight climate change and protect the environment. The late Aga Khan was given the title of "His Highness" by Queen Elizabeth in July 1957, two weeks after his grandfather, the Aga Khan III, unexpectedly made him heir to the family's 1,300-year dynasty as leader of the Ismaili Muslim sect.Over decades, the late Aga Khan evolved into a business magnate and a philanthropist, moving between the spiritual and the worldly with



ease.A defender of Islamic culture and values, he was widely regarded as a builder of bridges between Muslim societies and

the West despite — or perhaps because of — his reticence about becoming involved in politics.A network of hospitals bearing the Aga Khan's name is scattered in places where health care was lacking for the poorest, including Bangladesh, Tajikistan and Afghanistan, where he spent tens of millions of dollars in developing local economies.Ismailis lived for many generations in Iran, Syria and South Asia before also settling in east Africa, Central Asia and the Middle East, as well as Europe, North America and Australia more recently. They consider it a duty to tithe up to 12.5% of their income to the Aga Khan as steward. Shenila Khoja-Moolji, an associate professor at Georgetown University who researches Muslim societies, said Ismailis turn to the Aga Khan in matters of faith and daily life and often refer to him "as a paternal figure."

US Man, Convicted Of Pastor's Murder In 2011, Executed In Texas

Livingston, United States.A man was executed by lethal injection in the US state of Texas on Wednesday for the 2011 murder of a pastor that he insisted he did not commit, Steven Nelson, 37, spent more than a dozen years on death row for the murder of Clint Dobson, 28, during a robbery of the NorthPointe Baptist Church in Arlington, near Dallas.Dobson was beaten and suffocated with a plastic bag. Judy Elliott, the church secretary, was also badly beaten but survived.Nelson's appeals against his conviction and death sentence were repeatedly rejected by Texas courts and the US Supreme Court had declined to hear his case.He was executed and pronounced dead at 6:50 pm local time (0050 GMT on Thursday), state official Amanda Hernandez said in a statement. Nelson was interviewed by AFP recently at the maximum-security prison in Livingston, a town 75 miles (120 kilometers) north of Houston, where he was awaiting his execution."It's hard at times," he said. "You're waiting to be put to death. So that kind of breaks a little part of you every day... You just don't want to do nothing."Nelson

acknowledged that he served as a lookout during the robbery and that he entered the church after the murder to steal some items. But he said it was his two accomplices, who were never



brought to trial, who committed the murder."I didn't know what was going on on the inside," he said, claiming his friends "blamed everything on me." "So they're free and I'm locked up," he said. "I'm here on death row because of what somebody else did.""I'm an innocent man," Nelson said. "I'm being executed for a crim a murder, that I did not commit.""Make my heart stop"Nelson married a French woman, Helene Noa Dubois, while in prison, but said ahead of the execution that he

did not want her to witness it. "I really don't want her to see that -- me getting pumped full of drugs and being overdosed with drugs to kill me, to make my heart stop."But if she makes that choice to be there then that's her choice."In his final statement, Nelson said he was "at peace.""Always live for me and enjoy life," he said, according to state authorities. "Know I am not scared... I'm at peace, I'm ready to be at home."Let's ride Warden."There were 25 executions in the United States last year and Nelson's brought this year's number to two so far, after an earlier case in South Carolina. The death penalty has been abolished in 23 of the 50 US states, while three others -- California, Oregon and Pennsylvania -- have moratoriums in place.hree states -- Arizona, Ohio and Tennessee -- that had paused executions have recently announced plans to resume them. President Donald Trump is a proponent of capital punishment and on his first day in the White House he called for an expansion of its use "for the vilest crimes."

After US, Israel Halts Participation In UN Human Rights Council

Jerusalem. A day after US President Donald Trump announced America's withdrawal from the United Nations Human Rights Council (UNHRC), Israel's Minister of Foreign Affairs, Gideon Sa'ar, said on Wednesday that Israel would also join the US in its decision not to participate in the UNHRC.Sa'ar expressed Israel's support for Trump's decision, calling it a step in the right direction.In a post on X on Wednesday, Israeli Foreign Minister said, "Israel welcomes President Trump's decision not to participate in the UN Human Rights Council (UNHRC). Israel joins the United States and will not participate in the UNHRC."He called the UNHRC to have "traditionally protected human rights abusers by allowing them to hide from scrutiny, and instead obsessively demonizes the one democracy in the Middle East - Israel. This body has focused on attacking a democratic country and propagating antisemitism, instead of promoting human rights.""The discrimination against us

is clear: In the UNHRC, Israel is the only country with an agenda item dedicated solely to it. Israel has been subjected to over 100 condemnatory resolutions, over 20% of all resolutions ever passed in the Council - more than against Iran, Cuba, North Korea and Venezuela combined. Israel will not accept this discrimination any longer!" he added.The announcement from the Israeli Foreign Minister came amid Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to the United States. US President Trump made the announcement during a joint press conference with Israeli PM Netanyahu in Washington, DC on Tuesday (local time).Trump announced America's departure from the "anti-semitic" UN Human Rights Council and the UN Relief and Works Agency (UNRWA), which drew a lot of flak over the allegations of links with Hamas. "I'm also pleased to announce that this afternoon the United States withdrew from the anti-semitic UN Human Rights Council and ended all of the

support for the UN Relief and Works Agency, which funnelled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today I also took action to restore our maximum pressure policy on the Iranian regime. And we will once again enforce the most aggressive possible sanctions, drive Iranian oil exports to zero, and diminish the regime's capacity to fund terror throughout the region and the world," the US President added.tanyahu arrived in the US on Sunday to discuss the Gaza ceasefire agreement as well as plans for the Middle East with Trump, Al Jazeera reported.The Israeli PM is also expected to have a meeting with the US military leaders and members of Congress, Al Jazeera reported. These meetings will be held over several days.During the visit of the Israeli Prime Minister, Donald Trump said during the joint conference, "The bonds of friendship and affection between the American and Israeli people have endured for generations, and they are absolutely unbreakable."



waterway to the United States in a crisis. Panama has forcefully denied Trump's repeated allegations that China has been given a role in operating the canal. But it has also moved to address US concerns. President Jose Raul Mulino after his talks with Rubio said that Panama would not renew membership in the Belt and Road Initiative, Beijing's signature infrastructure-building program. Rubio told reporters on Monday that his talks with Mulino were "respectful" and that the visit was "going to achieve potentially good things that assuage concerns we have." Trump, however, said that he was still "not happy," although he acknowledged that Panama had "agreed to certain things."The United States and Panama are scheduled to hold new talks on Friday to discuss the canal. Trump in his inaugural address said the United States would be "taking back" the canal -- built more than a century ago by Washington with Afro-Caribbean labor and handed back to Panama at the end of 1999.

Following Trump, Argentina quits WHO; says 'would not allow international body to interfere in sovereignty'

The decision was based on "deep differences regarding health management, especially during the pandemic," President Javier Milei's spokesman told reporters.

BUENOS AIRES. Argentina said Wednesday it will pull out of the World Health Organization, following in the footsteps of the United States and citing similar complaints over the UN body's management of the Covid-19 pandemic. resident Javier Milei's spokesman announced the decision two weeks after President Donald Trump, an ideological ally and hero of the Argentine leader, announced Washington's planned exit from the agency. Milei's decision was based on "deep differences regarding health management especially during the pandemic," spokesman Manuel Adorni told reporters, adding Argentina would not "allow an international body to interfere in our sovereignty."He cited the "longest lockdown in the history of humanity" and "a lack of independence (at the WHO) in

the face of the political influence of some states," without naming names.Adorni insisted the measure gave Argentina "greater flexibility to implement policies adapted to the context" locally, while ensuring "greater availability of resources."HO data shows Argentina contributed some \$8.75 million in membership fees to the organization across 2022 and 2023 -- 0.11 percent of the total budget.It is slated to contribute \$8.25 million for the two-year 2024/25 cycle.he vast majority of the United Nations health agency's budget comes from voluntary contributions, however, and Argentina has made none in recent years.Adorni said Argentina "does not receive funding from the WHO, so this measure does not represent a loss of funds for the country."ast year, Argentina refused to join a new



pandemic protocol drawn up by the WHO and gave notice of its intention to withdraw from the agency altogether.Endless quarantines'A statement from the president's office, issued after Adorni's briefing, elaborated on the decision.It claimed the WHO had "promoted endless quarantines without scientific basis" as the world battled the Covid-19 pandemic, which claimed millions of lives.The

quarantines caused one of the greatest economic catastrophes in world history," the presidency said.Self-declared "anarcho-capitalist" Milei is an avowed fan of Trump, who signed an order within hours of his January 20 inauguration for the United States to withdraw from the WHO, which he has also criticized for its handling of the pandemic. Washington was the biggest contributor to the Geneva-based organization, which Trump claimed had "ripped us off," and the US withdrawal leaves global health initiatives short of funding.Since taking office in December 2023, Milei has gutted public spending, having vowed to maintain a zero budget deficit after years of overspending.His austerity measures are estimated to have tipped millions more people into poverty.



Newcastle, spurred on by a jubilant home crowd, managed the remainder of the match with ease, keeping Arsenal at bay and ensuring a return to Wembley. Their Brazilian captain, Bruno Guimarães, emphasized the importance of Jacob Murphy's opener, acknowledging the game-changing moment following Martin Odegaard's missed opportunity minutes earlier. With a ham carrying a slender 1-0 lead into the second leg against Liverpool at Anfield, Newcastle will now await the outcome to define their opponent in the final. For the fans and their passionate supporters, the ending of their long silverware drought remains very much alive.



I, Aparna Devi w/o Jay Ram Sahu, Resident of Gamharia, PO & PS- Arki, Dist- Khunti , Jharkhand vide affidavit no 196 dated 23.12.24. Declare that in my Adhar no . 585626715196, Banta Devi w/o Jay Ram Sahu also showing. My correct Name is Aparna Devi as affidavit for all purpose.